

separate legislation on the lines of the Madras Chit Funds Act, 1961, for regulating and controlling the working of chit funds in the State was brought to the attention of the State Government of Uttar Pradesh. The Government of Uttar Pradesh have advised that they have accepted in principle the need for legislation and that necessary action in this regard for enacting legislation is being taken.

(c) The Government of the States where chit fund business is popular have already enacted legislation or are taking steps to do so for regulating and controlling this business. The need for any such intervention in the matter by the Central Government has not, therefore, arisen.

#### भारत में विदेशी स्वयंसेवक

2022. श्री बंश नारायण सिंह :  
श्री रामगोपाल शालवाले :  
श्री शारदानन्द :  
श्री जगन्नाथ राव जोशी :  
श्री श्रींकार लाल बेरवा :  
श्री हुकम चन्द कछुवाय :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की करेंगे कि :

(क) देश में इस समय विदेशी स्वयंसेवक कार्यक्रम के अन्तर्गत कार्य करने वाले विदेशी स्वयंसेवकों की संख्या कितनी है ; और

(ख) प्रत्येक देश के कितने कितने विदेशी स्वयंसेवक हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बिद्या चरण शुक्ल) : (क) इस समय देश में विदेशी स्वयंसेवकों की कुल संख्या 753 है ।

(ख) इन स्वयंसेवकों का देशवार व्यौरा इस प्रकार है :—

संयुक्त राज्य अमेरिका  
(अमरीकी शान्ति दल)

— 443

पश्चिम जर्मनी (जर्मनी स्वयंसेवक सेवा)	—107
ब्रिटेन (समुद्रपारीय स्वयंसेवक सेवा)	—88
जापान (जापानी समुद्रपारीय सहयोग स्वयंसेवक)	—57
डेनमार्क (डेनिश स्वयं सेवक सेवा)	—34
कनाडा (कनाडा विश्व-विश्वालीन समुद्रपारीय सेवा)	—13
स्वीडन (स्वेलीज)	—11

#### राष्ट्रीय आय में वार्षिक वृद्धि की दर

2023. श्री श्रींकार लाल बेरवा :  
श्री बंश नारायण सिंह  
श्री भारत सिंह चौहान :  
श्री जगन्नाथ राव जोशी :  
श्री रामावतार शर्मा :  
श्री यशवन्त सिंह कुशवाह :  
श्री शारदा नन्द :  
श्री हुकम चन्द कछुवाय :  
श्री रामगोपाल शालवाले :  
श्री श्रीम प्रकाश त्यागी :  
श्री न० र० देवघरे :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि 1967-68 में राष्ट्रीय आय में वार्षिक वृद्धि की दर 8.9 प्रतिशत थी जबकि 1968-69 में वह केवल 1.9 प्रतिशत रह गई है ;

(ख) यदि हाँ, तो इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(ग) इस सम्बन्ध में क्या कदम उठाये गये तथा उनके क्या परिणाम निकले हैं और इस

सम्बन्ध में भविष्य का क्या कार्यक्रम निश्चित किया गया है ?

बिस्व मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्या चरण शुक्ल) : (क) जी हाँ ।

(ख) और (ग). राष्ट्रीय आय की दर में हर साल जो परिवर्तन होते रहते हैं वे काफी हद तक, मौसम की स्थिति के अनुसार कृषि के उत्पादन में होने वाली घट-बढ़ के परिणाम-स्वरूप होते हैं, जिसके कारण राष्ट्रीय आय में होने वाली वृद्धि की प्रवृत्ति बढ़ती या घटती रहती है । 1967-68 का वर्ष, दो वर्ष तक सूखा पड़ने के बाद का ऐसा वर्ष था जिसमें कृषि उत्पादन में अपेक्षाकृत काफी वृद्धि हुई । 1967-68 के दौरान राष्ट्रीय आय में जिस ऊँची दर से वृद्धि हुई वह 1968-69 में जारी न रह सकी क्योंकि इस वर्ष मौसम अपेक्षाकृत कुछ प्रतिकूल रहा था । लेकिन औद्योगिक स्थिति को फिर से सुधारने के लिए सरकार ने जो विभिन्न कदम उठाए और कृषि उत्पादन को बढ़ाने के लिए जो लगातार प्रयत्न किये उनके परिणामस्वरूप राष्ट्रीय आय में, 1968-69 में हुई वृद्धि की दर की अपेक्षा 1969-70 में काफी ऊँची दर से वृद्धि होने की संभावना है ।

चौथी पंचवर्षीय आयोजना में राष्ट्रीय आय में लगभग 5.5 प्रतिशत की वार्षिक दर से वृद्धि होने की परिकल्पना की गयी है । इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए आवश्यक कार्यक्रमों और नीतियों का उल्लेख आयोजना की पुस्तिका में किया गया है ।

#### Plans for Expansion of Family Planning

2024. SHRI V. NARASIMHA RAO :  
SHRI SITARAM KESRI :  
SHRI D. N. PATODIA :  
SHRI G. VENKATASWAMY :

Will the Minister of HEALTH AND FAMILY PLANNING AND WORKS,

HOUSING AND URBAN DEVELOPMENT be pleased to state :

(a) the broad outlines of the new expansion plans for the family planning ; and

(b) the total amount of foreign aid received so far in respect of this programme ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY PLANNING, AND WORKS, HOUSING AND URBAN DEVELOPMENT (SHRI B. S. MURTHY) : (a) Besides the expansion of the programme envisaged in the Fourth Five Year Plan, proposals for acceleration of the Family Planning Programme subject to the availability of external aid, include—

- (i) opening of more rural sub-centres so as to have a sub-centre for every 10,000 population,
- (ii) provision of working and residential accommodation at most of the rural main centres and sub-centres,
- (iii) intensive Family Planning work with increased inputs in another 17 or more districts and certain selected areas,
- (iv) opening another 92 Post-partum Centres,
- (v) providing more and improved training facilities for Auxiliary Nurse Midwives and other categories of personnel,
- (vi) increasing research activity and improving evaluation machinery, and
- (vii) increasing immunisation and nutritional components for spreading the Family Planning message through assurance of longevity of the mothers and children.